eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

डिजिटल विभाजन और वंचित बच्चों की शिक्षाः वर्तमान संकट एवं समाधान

रागिनी राय[1], डॉ0 स्मिता सिंह[2]

[1]शोधार्थी शिक्षाशास्त्र विभाग, महिला महा0, बस्ती, सम्बद्ध–सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
[2]शोध निर्देशक, सहयुक्त आचार्य, महिला महाविद्यालय, बस्ती

Received: 21 April 2026 Accepted & Reviewed: 25 April 2026, Published: 30 April 2026

Abstract

डिजिटल विभाजन समकालीन विश्व की एक गंभीर सामाजिक–शैक्षिक समस्या है, जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक असमान पहुँच के कारण उत्पन्न होती है। यह विभाजन विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से पिछड़े एवं वंचित बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर रहा है। कोविड–19 महामारी के दौरान जब शिक्षा पूर्णतः ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भर हो गई, तब यह समस्या और स्पष्ट रूप से सामने आई। प्रस्तुत शोध–पत्र में डिजिटल विभाजन की अवधारणा, उसके आयाम, वंचित बच्चों पर प्रभाव, भारतीय संदर्भ में वर्तमान स्थिति, सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयासों तथा संभावित समाधानों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और शैक्षिक समानता से जुड़ा हुआ मुद्दा हैं।

मुख्य शब्दः विभाजन, वंचित बच्चे, ऑनलाइन शिक्षा, आईसीटी, शैक्षिक असमानता

Introduction

21वीं सदी को 'डिजिटल युग' कहा जाता है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बैकिंग, शासन और सामाजिक जीवन का बड़ा भाग डिजिटल तकनीकों पर आधारित है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, टैबलेट और कम्प्यूटर जैसे उपकरणों ने शिक्षा के स्वरूप को बदल दिया है। विशेषकर कोविड–19 महामारी के दौरान, जब विद्यालय बंद हुए, तब ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प बन गई। किन्तु यह डिजिटल क्रांति सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच सकी। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण, अनुसूचित जाति–जनजाति, अल्पसंख्यक तथा दिव्यांग वर्ग के बच्चों को डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित होना पड़ा। इसी असमानता को 'डिजिटल विभाजन' कहा जाता है। डिजिटल विभाजन शब्द को व्यापक रूप से वैश्विक संस्थाओं जैसे इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन और यूनिसेफ द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार ''डिजिटल विभाजन केवल इंटरनेट की उपलब्धता का प्रश्न नहीं है, बल्कि डिजिटल कौशल, गुणवत्ता पूर्ण सामग्री और सुरक्षित उपयोग की क्षमता से भी जुड़ा हुआ है।'' भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, डिजिटल विभाजन एक जटिल सामाजिक समस्या बन चुका है।

डिजिटल विभाजन की अवधारणा– डिजिटल विभाजन उस अन्तर को दर्शाता है जो समाज के विभिन्न (गरीब–अमीर, शहरी–ग्रामीण, शिक्षित–अशिक्षित विकसित व विकासशील देश) लोगों के बीच डिजिटल संसाधन जैसे तकनीकी, इंटरनेट और सूचना–संचार साधनों तक पहुँच में असमानता। अर्थात समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते है जिनके पास आधुनिक तकनीक (जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट आदि) तक उनकी न तो पहुँच होती है और न ही वे इनका प्रयोग करना जानते है क्योंकि उनके पास संसाधन नही होते।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

यह अन्तर केवल संसाधनों की उपलब्धता तक सीमित नही है बल्कि उनका तकनीकी ज्ञान में दक्ष न होना, डिजिटल साक्षरता में कमी और उनका प्रयोग न कर पाना भी शमिल होता है। हमारे समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी है जिनके पास संसाधन भी पर्याप्त है और उनके प्रयोग का तकनीकी ज्ञान भी हैं, जबकि कुछ लोग इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। इसी अंतर को डिजिटल विभाजन कहा जाता है।

इस प्रकार डिजिटल विभाजन को मुख्यतः तीन स्तरों में बाटाँ जा सकता है।

प्राथमिक स्तर– यह विभाजन डिजिटल संसाधन जैसे इण्टरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता से सम्बन्धित होता है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज में कमी बिजली की अनियमित्तता और उपकरणों की महंगाई शामिल है। कुछ लोगो के पास कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और इण्टरनेट का अभाव इस विभाजन को और बढ़ाता है।

द्वितीय स्तर– इसमें लोगो के पास डिजिटल उपकरण तो होते है किन्तु इनका सही उपयोग करना नही आता। डिजिटल साक्षरता, तकनीकी, कौशल और डिजिटल सामग्री के प्रयोग की दक्षता व साक्षरता की कमी के कारण व्यक्ति तकनीकी का पूरा लाभ नही ले पाता।

तृतीय स्तर– इसमें डिजिटल संसाधनों के उपयोग से किसे कितना लाभ मिल रहा है और किसे लाभ नही मिल रहा है, इससे सम्बन्धित होता है। उच्च आय वर्ग के बच्चे ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल पुस्तकालय, ई–लर्निंग, प्लेटफार्म का प्रयोग कर लाभ उठाते है जबकि समाज में गरीब व वंचित वर्ग के बच्चे संसाधनों की कमी के कारण पिछड़ जाते है जिससे डिजिटल असमानता पैदा होती है।

भारतीय संदर्भ में डिजिटल विभाजन– भारत में भी डिजिटल पहुँच में पिछले कुछ दशकों में अत्यधिक वृद्धि हुई है परन्तु डिजिटल असमानता अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट 2019–20 के अनुसार ग्रामीण भारत में केवल 15.20 प्रतिशत परिवारों के पास इण्टरनेट की नियमित सुविधा उपलब्ध थी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक था।

एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021–22 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बच्चों के पास व्यक्तिगत स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं था। कई बच्चों को परिवार के एक ही मोबाइल पर निर्भर रहना पड़ता था। यह असमानता डिजिटल विभाजन को दर्शाती है।

कोविड–19 की महामारी के दौरान, जब विद्यालय बंद हुए तब शिक्षा ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर हो गई। इससे डिजिटल विभाजन स्पष्ट रूप से सामने आया। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन, डेटा बैंक या इण्टरनेट कनेक्शन नही था, वे शिक्षा से कट गये।

यूनेस्कों की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर करोड़ों बच्चे डिजिटल संसाधनों के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह गये। भारत में भी लाखों बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई।

डिजिटल विभाजन के प्रमुख कारण

- **आर्थिक स्थिति–** डिजिटल विभाजन का सबसे प्रमुख कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति होती है। जिन परिवारों के पास स्मार्टफोन, कम्प्यूटर, टैबलेट, इण्टरनेट आदि सेवाओं को खरीदना सम्भव नही होता, वे

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

डिजिटल साक्षरता से वंचित रह जाते और उनकी ऑनलाइन शिक्षा प्रभावित होती है। जिन परिवारों के पास संसाधन पर्याप्त होते है वो तकनीकी ज्ञान का लाभ उठा पाते है।

- **परिवेश सम्बन्धी अन्तर–** ग्रामीण और शहरी परिवेश में डिजिटल साक्षरता में काफी अन्तर पाया जाता है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रो के लोग डिजिटल साक्षरता कम पायी जाती है क्योंकि वहाँ नेटवर्क की समस्या और बिजली की अनियमित्तता के कारण डिजिटल शिक्षा प्रभावित होती है।
- **डिजिटल साक्षरता की कमी–** गरीब परिवारों के अभिभावकों को डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करना नही आता जिससे वे अपने बच्चों को डिजिटल उपकरणों को प्रयोग करना नही सीखा पाते। परिणाम स्वरूप डिजिटल साक्षरता में कमी आती है।
- **तकनीकी उपकरणो की कमी–** आज भी अनेक ऐसे विद्यालय है जिनके कम्प्यूटर लैब में इण्टरनेट और डिजिटल शिक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा में नही उपलब्ध है जिससे प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त मात्रा में डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नही मिल पाता।
- **लैंगिक असमानता–** आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार है जहाँ लड़कियों को लड़कों की तुलना में तकनीकी शिक्षा एवं उपकरणों के प्रयोग की अनुमति कम दी जाती है जिससे लड़कियाँ डिजिटल शिक्षा में पिछड़ जाती है।
- **भाषा सम्बन्धी समस्या–** डिजिटल प्लेटफार्म पर अधिकांश शिक्षण समग्री अंग्रेजी में उपलब्ध होता है जिससे भारत जैसे विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों को डिजिटल माध्यम से सीखने में असुविधा होती है। हिन्दी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षण समग्री की कमी के कारण वंचित बच्चों को डिजिटल प्लेटफार्म पर अध्ययन करने में कठिनाई महसूस होती है।
- **वंचित बच्चों पर डिजिटल विभाजन का प्रभाव**
- **मानसिक और सामाजिक प्रभाव–** डिजिटल संसाधनों की कमी से वंचित बच्चो में आत्म विश्वास में कमी, निराशा और सामाजिक अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। वही जिन बच्चों को अत्यधिक डिजिटल संसाधनों के प्रयोग का अवसर मिला वो अत्यधिक समय तक ऑनस्क्रीन रहने के कारण उनमें डिजिटल लत की समस्या देखी गयी जिससे उनके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है।
- **शिक्षा में असामानता–** डिजिटल संसाधनों के अभाव के कारण वंचित बच्चे ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षण सामग्री से वंचित रह जाते है जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है।
- **सीमित शैक्षिक अवसर–** डिजिटल माध्यम से छात्रो को सीखने के विभिन्न अवसर जैसे विडियों, ई–बुक और इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री मिलती रहती है। इन संसाधनों के अभाव में वंचित बच्चों को सीखने का अवसर सीमित हो जाता है।
- **रोजगार के कम अवसर–** डिजिटल साक्षरता के अभाव में वंचित बच्चे अन्य बच्चों से पिछड़ जाते है इसलिए उन्हें रोजगार के कम अवसर प्राप्त होते है यदि इन बच्चों को प्रारंभ से ही डिजिटल शिक्षा मिलती तो इनको भी अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते।

सरकारी प्रयास और नीतियाँ– भारत सरकार डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए अनेक पहल की है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

• **डिजिटल इंडिया अभियान** – यह भारत सरकार की एक महत्त्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरूआत 01 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा किया गया जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थ व्यवस्था में बदलना तथा प्रत्येक नागरिक तक डिजिटल सेवाओं को पहुँचाना है, साथ ही सरकारी सेवाओं को पारदर्शी एवं सुलभ बनाना है।

• **राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन** – वर्ष 2014 और 2016 के बीच भारत सरकार ने तकनीकी के क्षेत्र में दो महत्त्वपूर्ण योजनाएं चलायी। पहला राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन और दूसरा डिजिटल साक्षरता अभियान जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी सहित 52.5 लाख व्यक्तियो को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना था। इन पहल के तहत दिये गये प्रशिक्षण से 53.67 लाख प्रतिभागियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसमें लगभग 42 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों से थे।

• **राष्ट्रीय कौशल विकास निगग**– डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने व्हाट्सएप और लिंक्डइन जैसी तकनीकी लोगों के साथ साझेदारी कर ''डिजिटल स्किल चैपियंस'' प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है। यह सहयोग वंचित बच्चों एवं युवाओं को महत्त्वपूर्ण डिजिटल दक्षताओं से लैस करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये भी प्रयास सामूहिक रूप से डिजिटल समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने में भारत की सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित करता है। जो तकनीकी रूप से समावेशी भविष्य की ओर संकेत करता है।

• **भारत नेट परियोजना** – डिजिटल विभाजन के प्रति ग्रामीण समूदायों की संवेदनशीलता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने 25.10.2011 को राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (N.O.F.N.) जिसे अब भारत नेट परियोजना कहा जा रहा है, की शुरूआत की। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर उच्च गति वाला ब्रांडबैण्ड पहुँचाने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि ब्लॉक मुख्यालयों को ग्राम पंचायतों से ब्रांडबैण्ड के द्वारा जो़ड़ा जा सके।

• **दीक्षा प्लेटफार्म** – डिजिटल विभाजन को कम करने और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 05 सितम्बर 2017 को एक ऑनलाइन प्लेटफार्म दीक्षा पोर्टल को लांच किया। यह ऐप शिक्षकों छात्रों और अभिभावकों को पर्याप्त मात्रा में डिजिटल शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराता है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं के अध्ययन सामग्री विभिन्न क्षेत्रिय भाषाओं में उपलब्ध होती है वंचित वर्ग के छात्र इस प्लेटफार्म का प्रयोग कर अपनी शिक्षा जारी रख सकते है।

• **पी0एम0ई–विद्या** –पी0एम0ई–विद्या के अन्तर्गत टीवी, चैनल, रेडियो और ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री को विभिन्न डिजिटल माध्यमों के द्वारा छात्रों तक पहुँचायी जा रही है, यह भारत सरकार की एक नई एवं अनोखी पहल है। इन पहल के बावजूद भी भारत में बहुत से ऐसे परिवार है, जिनके पास डिजिटल उपकरणों की कमी और डिजिटल साक्षरता की समस्या अभी भी बनी हुई है। जिसके समाधान के लिए सरकार को निम्नलिखित समाधान करना चाहिए।

• **गैर–सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र**–डिजिटल असामानता की खाई को कम करने के लिए निजी क्षेत्र और गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। कई संगठन वंचित बच्चों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से नई पहल करके अपनी कार्पोरेट जिम्मेदारी को पूरा करते है। इनके

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

प्रयासों से वंचित बच्चों को संसाधन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जिससे बदलते परिवेश में उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त होता है।

कम्प्यूटर शिक्षा नामक एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा इण्डिया डेवलपमेंट एण्ड रिलिफ फण्ड के सहयोग से शूरू किया गया एक अनुकरणीय प्रयास डिजिटल विभाजन को पाटने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। यह पहल सरकारी और नगरपालिका विद्यालयों में पढ़ने वाले वंचित बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाले कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करती है। वर्ष 2013 में मात्र 15 लैपटॉप से शूरू हुआ यह कार्यक्रम अब तक उल्लेखनीय योगदान दे चुका है और वर्तमान समय में यह 16 राज्यों में एक लाख से अधिक बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र, गैर–सरकारी संगठन और सरकार के बीच सहयोग की क्षमता को कम करके नही आंका जा सकता। इनके आपसी ताल–मेल से एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण को सम्भव बनाया जा सकता है, जिसके प्रत्येक प्रयास से अधिकतम प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।

समाधान एवं सिफारिशें– डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए निम्नलिखित अनुशंसाओं की आवश्यकता है।

- **सतत् निवेश–** सरकार को डिजिटल बुनियादी ढ़ाँचे के लिए संसाधन आवंटित करने चाहिए, जिससे सभी लोगों के लिए कम खर्च में इण्टरनेट और उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित किया जा सकें।
- **डिजिटल अवसंरचना का विस्तार–** वंचित वर्ग के बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल अवसंरचना का विस्तार जन–जन तक होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट कनेक्विटी और बिजली आपूर्ति को मजबूत करना आवश्यक है।
- **संसाधनों की उपलब्धता–** ऐसे परिवार जो डिजिटल उपकरणों को खरीदने में असमर्थ है उन्हे टैबलेट या लैपटॉप उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि वे अपनी आगे की शिक्षा जारी रख सकें।
- **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम–** डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर छात्रो, शिक्षकों और अभिभावकों को डिजिटल संसाधनों के प्रयोग का प्रशिक्षण देते रहना चाहिए जिससे कि वे इन उपकरणों के प्रयोग में और निपुण हो सके तथा नवीन तकनीको को जान सकें।
- **हाइब्रिड मॉडल–** सभी विद्यालयों में शिक्षण कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रित रूप अपनाना चाहिए ताकि वे आधुनिक तकनीकी को भी सीख सकें और उनका नैतिक व सामाजिक विकास भी हो सकें।
- **सामुदायिक डिजिटल केन्द्र–** गाँव और कस्बों में सामुदायिक डिजिटल केन्द्र स्थापित करना चाहिए, जहाँ बच्चे इंटरनेट और कम्प्यूटर का प्रयोग करना सीख सकें।
- **लैंगिक समानता पर ध्यान–** लैंगिक भेद को समाप्त करके लड़कियों को भी डिजिटल शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करना चाहिए।
- **जागरूकता कार्यक्रम–** सामुदायिक स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगो को डिजिटल तकनीकी के महत्त्व व उपयोग पर जानकारी देनी चाहिए।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED, INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 04, April 2026

- **समावेशिता–** डिजिटल सशक्तिकरण प्रयासों में सभी समुदायों, बालिकाओं, दिव्यांग लोगों को शामिल करके समावेशन को बढ़ाया जा सकता है।
- **निगरानी और सुधार–** समावेशन सम्बन्धी पहल का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए और समय–समय पर होने वाली कमियों को दूर करके इष्ट्म संसाधनों के द्वारा सुधार करना चाहिए।

वंचित बच्चों को डिजिटल कौशल और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करके सशक्त बनाना, आसमानता को कम करता है और अधिक समावेशी भविष्य को बढ़ावा देता है। सरकार संस्थानों और व्यक्तियों को समूहिक प्रयास के द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है जहाँ प्रत्येक बच्चा डिजिटल युग में आगे बढ़ सकें।

निष्कर्ष– डिजिटल विभाजन केवल तकनीकी समस्या नही बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानवाधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वंचित वर्गो की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल विभाजन एक गंभीर चुनौती है। यदि इस समस्या का समाधान नही किया गया तो समाज में शैक्षिक और सामाजिक असामनता और अधिक बढ़ सकती है। इसलिए वंचित बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता और सरकार की प्रभावी नीतियों के माध्यम से इस अन्तर को कम किया जा सकता है। इसमें सरकार शिक्षक और निजी क्षेत्रों को मिलकर कार्य करना होगा। यादि डिजिटल संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित किया जाये तो यह शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, अन्यथा यह असमानता की खाई को और बढ़ा सकती है। जब सभी बच्चों को समान रूप से डिजिटल शिक्षा के अवसर मिलेगे, तभी शिक्षा का वास्तविक उददे्श्य–''समानता और समावेश'' पूरा हो सकेगा।

सन्दर्भ सूची–

- यूनिसेफ (2023): द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रेन रिपोर्ट
- यूनेस्को (2022): ग्लोबल एजूकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट
- नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (2020): हाउसहोल्ड सोशल कंजम्पसन रिपोर्ट
- https://usof.gov.in
- https://www.drishtiias.com
- ऐनूअल स्टेट्स ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट (2022): ए0एस0इ0आर0 रूरल रिपोर्ट
- डिजिटल इण्डिया (2015): गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया
- भारत नेट (2011): मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिकेशन, इण्डिया
- दीक्षा पोर्टल डाक्यूमेन्टेशन
- पी0एम0ई–विद्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया